strategy of labour leadership is to bring about industry-wise work stoppage in order to raise the wage level ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी भूमि पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की परेड करने पर प्रतिबन्ध

*495. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा सरकारी बस्तियों में सरकारी भूमि पर परेड आदि को जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारी इंजीनियरी निगम, हटिया में साम्प्रदायिक दंगों के बाद भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा वहां पर परेड का करना जारी है ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने देने के क्या कारण है ; और

(घ) इस बारे में सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Modipon Ltd.

*496. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the annual report on Modipon's functioning in which the Directors complain of a "steep decline" in prices and yet show a turnover of Rs. 7.61 crores, a gross profit of Rs. 2.05 crores, a return of 27 per cent on sales and 102 per cent on share capital ;

(b) whether the capacity of this Company was allowed to be raised by Government from 1,800 to 2,200 tonnes per annum ;

(c) whether this Compay gave Rs. 25,000 donation to the Congress Party and an equal sum to the A. I. C. C as unsecured loan ;

(d) whether this Company and others have raised prices of nylon yarn after February, 1969 ; and

(e) if so, the reasons for not taking stern action against this company and others for putting up prices of nylon yarn after February, 1969 ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes Sir, but the normal practice of price fixation bodies like the Tariff Commission and the Government is to relate profits to capital employed and on this basis in the annual report referred to, the profit works out to 14% on capital employed.

(b) A letter of intent was issued on 7.6.1969 for this expansion.

(c) It has been so reported in the annual accounts of the company for 1968-69.

(d) and (e). Prices of nylon which were on an average Rs 100 for 15 denier and Rs. 94 for 20 denier monofilaments in April, 1968, came down to Rs. 76 and Rs. 70 respectively in February, 1969 and have since increased to Rs. 81 and Rs. 75 respectively in September, 1969. Government have been concerned about this increase and have discussed this with spinners, the users as represented by the Association of Man-Made Fibre Industry as also with other concerned Ministries. The following action has been taken so far :—

(i) The Tariff Commission who were requested in July, 1968, to report on the Fair Price for man-made fibres and yarn, have been requested to expedite their report.

(ii) STC have been permitted to import 750-1000 tonnes of nylon yarn this year to alleviate the shortage of nylon yarn. The creation of

a revolving fund to permit the import of further quantities of nylon yarn to meet the demand for exports of art silk fabrics is also under consideration.

(iii) In the light of meetings convened by the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals in the matter and advice given, the Textile Commissioner has had further discussions with spinners and weavers to arrive at satisfactory arrangements for keeping prices at a reasonable level and to ensure an equitable and uniform distribution to consumers to avoid malpractices.

(vi) Further action is contemplated in the context of (iii) and (i). It would not be in the public interest to disclose what this will be at this stage.

(v) It has also been proposed to create additional capacity for the production of nylon and to give preference to cooperatives of nylon weavers, and State Industrial Corporations. The pattern of future demand is being analysed taking into account the installation of further power looms in backward areas so as to select areas where such capacity should be erected.

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

497. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार, किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन आदेशों को केवल तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कार्यालयों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रेकार्ड सार्टर, दफ्तरी, चपरासी और फर्राश ।

(ख) जी हां ।

(ग) अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध प्रशासनिक खर्च में किफायत लाने और फालतू कर्मचारियों को समाहित करने के विचार से लगाया गया है । राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में स्थायी संवर्गों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम संख्या में अधिकारियों की भर्ती की जाती है और उनके फालतू होने की संभावना नहीं है ।

पश्चिम रेलवे (पश्चिम खण्ड) के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

*498. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे (पश्चिम खण्ड) के कर्मचारियों ने महा प्रबन्धक को चालू वर्ष में ऐसा कोई ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन में उल्लिखित कठिनाइयों के सम्बन्ध में उन्होंने कोई जानकारी एकत्रित की है ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कारों के निर्माण की लागत के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*499. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर कारों की